साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 04-10 मार्च 2024 वर्ष-9, अंक-46
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समीक्षा में दिए निर्देश, सर्वेक्षण और राहत के लिए जिलों में प्रक्रिया प्रारंभ

» किसान बोले-बारिश और ओलावृष्टि से फसलें हो गई खराब

» राजस्व महाअभियान की अवधि अब 10 मार्च तक

ओलावृष्टि से आहत किसानों को प्रदेश सरकार देगी राहत प्रभावित फसलों का सर्वे करने खेतों में उतरे पटवारी

जागत गांव हमार, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हाल ही में कुछ जिलों में हुई ओलावृष्टि के दृष्टिगत सर्वेक्षण सहित प्रभावित किसानों को राहत के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने गत दिवस इस संबंध में प्रमुख सचिव राजस्व और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। समीक्षा में जानकारी दी गई कि प्रभावित जिलों में किसानों के हित में आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सीएम ने कहा कि गत 15 जनवरी से प्रारंभ किए गए राजस्व महाअभियान को 29 फरवरी तक संचालित करने के निर्देश दिए गए थे। अभियान में अब तक 1.65 लाख प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। कुल 2.5 लाख नए प्रकरणों को दर्ज किया गया था। इसके साथ ही दो लाख 14 हजार समय सीमा पार वाले लंबित प्रकरणों का निराकरण भी किया गया है। अभियान से आमजन को काफी राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने अभियान की अवधि 10 मार्च तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

हर जिले में नुकसान | इधर, प्रदेश में बेमौसम वर्षा ने जिलेभर में फसलों को प्रभावित किया। ओलावृष्टि के बाद राजस्व और कृषि विभाग ने फसलों का सर्वे शुरू कर दिया है। अधिकारी सर्वे के बाद रिपोर्ट मिलने पर नियमानुसार मुआवजा राशि देने की बात कह रहे हैं। ओलावृष्टि से हर जिले में ज्यादा नुकसान हुआ है। पटवारियों को खेतों में भेजकर फसल नुकसानी का सर्वे शुरू करा दिया है। नुकसानी के आंकलन की रिपोर्ट शासन को भेजेंगे।

- राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 26-27 फरवरी को असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति का सर्वे समय सीमा में करें। सर्वेक्षण संवेदनशीलता के साथ किया जाए।
  करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री
- ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को मिलेगा। किसानों के साथ सरकार हर कदम पर खड़ी है। मुख्यमंत्री ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। किसान चिंता ना करें।
  ऐदल सिंह कंषाना, कृषि मंत्री

फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान हुआ जारी

रबी सीजन का उत्पादन 144.61 लाख मीट्रिक टन होगा

देश में गेहूं और चावल के उत्पादन का टूटा रिकॉर्ड

जागत गांव हमार, भोपाल।

केंद्र सरकार ने गेहूं के बंपर उत्पादन का अनुमान लगाया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि 2023-24 में गेहूं का उत्पादन 1120.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 1105.54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख मीट्रिक टन अधिक है। इस साल खरीफ चावल उत्पादन 1114.58 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है जो 2022-23 के 1105.12 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.46 लाख टन अधिक है। रबी चावल का उत्पादन 123.57 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के प्रमुख (खरीफ और रबी मौसम) फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। पिछले कृषि वर्ष से, जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है। इसलिए इस वर्ष क्षेत्र, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में केवल दो मौसम यानी खरीफ और रबी मौसम शामिल हैं। इसलिए इस वर्ष क्षेत्र, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में केवल दो मौसम यानी खरीफ और रबी मौसम शामिल हैं। यह अनुमान मुख्य रूप से राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। प्राप्त आंकड़ों को रिमोट सेंसिंग, साप्ताहिक फसल मौसम निगरानी समूह की रिपोर्ट और अन्य एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के साथ मान्य किया गया है। अनुमान तैयार करते समय जलवायु परिस्थितियों, पिछले रुझानों, मूल्यों में उतार-चढ़ाव, मंडी आगमन आदि पर भी विचार किया जाता है।

श्री अन्न का रिकॉर्ड उत्पादन | खरीफ सीजन के श्री अन्न का उत्पादन 128.91 लाख मीट्रिक टन और रबी सीजन के श्री अन्न का उत्पादन 24.88 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। खरीफ ज्वार का उत्पादन 15.46 लाख मीट्रिक टन और रबी ज्वार का उत्पादन 24.88 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से अधिक है। मोटे अनाज (खरीफ) का उत्पादन 356.11 लाख मीट्रिक टन और रबी सीजन का उत्पादन 144.61 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है।

दलहन उत्पादन निराशाजनक | तूअर का उत्पादन 33.39 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है जो पिछले साल के उत्पादन 33.12 लाख मीट्रिक टन के लगभग बराबर है। तूअर की कटाई अभी भी जारी है, अनुमानों में और बदलाव हो सकते हैं। चने का उत्पादन 121.61 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के चने के उत्पादन कम है, लेकिन औसत (2018-19 से 2022-23) से अधिक है। मसूर का उत्पादन 16.36 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है।

नहीं बढ़ा सरसों उत्पादन

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार सोयाबीन का उत्पादन 125.62 लाख मीट्रिक टन और सरसों का उत्पादन 126.96 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के उत्पादन के लगभग बराबर है। हालांकि औसत उत्पादन से 20.57 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कपास का उत्पादन 323.11 लाख गांठे (प्रत्येक 170 किलोग्राम) और गन्ने का उत्पादन 4464.30 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है।

जायद फसलों का अनुमान कब

खरीफ फसलों के उत्पादन अनुमान तैयार करते समय फसल कटाई प्रयोग आधारित उपज पर विचार किया गया है। हालांकि, राज्य अभी भी खरीफ़ सीसीई के परिणामों को संकलित करने की प्रक्रिया में हैं। कुछ फसलों जैसे तूर, गन्ना, अरंडी आदि की सीसीई अभी भी जारी है। रबी फसलों का उत्पादन प्रारंभिक बोए गए क्षेत्र की रिपोर्ट और औसत उपज पर आधारित है। इसलिए, सीसीई के आधार पर बेहतर उपज अनुमान प्राप्त होने पर ये आंकड़े बदल सकते हैं। विभिन्न जायद फसलों का उत्पादन आगामी तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया जाएगा।

खरीफ-रबी फसलों का उत्पादन

- खरीफ सीजन का कुल खाद्यान्न उत्पादन 1541.87 लाख मीट्रिक टन होगा
- रबी सीजन का कुल खाद्यान्न उत्पादन 1551.61 लाख मीट्रिक टन होगा
- खरीफ चावल उत्पादन 1114.58 लाख मीट्रिक टन होगा
- रबी चावल उत्पादन 123.57 लाख मीट्रिक टन होगा
- गेहूं उत्पादन 1120.19 लाख मीट्रिक टन होगा
- खरीफ मक्का उत्पादन 227.20 लाख मीट्रिक टन होगा
- रबी मक्का उत्पादन 97.50 लाख मीट्रिक टन होगा
- खरीफ श्री अन्न उत्पादन 128.91 लाख मीट्रिक टन होगा
- रबी श्री अन्न उत्पादन 24.88 लाख मीट्रिक टन होगा
- तूर उत्पादन 33.39 लाख मीट्रिक टन होगा
- चना उत्पादन 121.61 लाख मीट्रिक टन होगा
- खरीफ तिलहन उत्पादन 228.42 लाख मीट्रिक टन होगा
- रबी तिलहन उत्पादन 137.56 लाख मीट्रिक टन होगा
- सोयाबीन उत्पादन 125.62 लाख मीट्रिक टन होगा
- सरसों उत्पादन 126.96 लाख मीट्रिक टन होगा
- गन्ना उत्पादन 4464.30 लाख मीट्रिक टन होगा
- कपास उत्पादन 323.11 लाख गांठ होगा
- जूट उत्पादन 92.17 लाख गांठ होगा

किसानों की सहायता के लिए तीन नए ग्रेड भी जोड़े

केंद्र सरकार ने बढ़ाई खाद पर मिलने वाली सब्सिडी

जागत गांव हमार, भोपाल।

केंद्र सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 24,420 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएंडके की सब्सिडी पर मुहर लगाई है। अप्रैल से सितंबर तक चलने वाले 2024-25 खरीफ सीजन के दौरान किसानों को उर्वरक की खरीदारी पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि इसमें किसानों की सहायता और तिलहन व दालों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए तीन नए ग्रेड भी जोड़े गए हैं। वहीं, कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वैश्विक बाजार में उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के बावजूद, हमने कीमतों को पिछले सीजन की तरह ही रखने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा कि 2024 के खरीफ सीजन के लिए नाइट्रोजन (एन) पर सब्सिडी 47.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फॉस्फेटिक (पी) पर 28.72 रुपए प्रति किलोग्राम, पोटाश (के) पर 2.38 रुपए प्रति किलोग्राम और सल्फर (एस) पर 1.89 रुपए प्रति किलोग्राम तय की गई है।

डीएपी पर 4,500 रुपए टन सब्सिडी

फॉस्फेटिक उर्वरकों पर सब्सिडी 2023 रबी सीजन के लिए 20.82 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 2024 खरीफ सीजन के लिए 28.72 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है। हालांकि, 2024 खरीफ सीजन के लिए नाइट्रोजन (एन), पोटाश (के) और सल्फर (एस) पर सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर सब्सिडी 4,500 रुपए प्रति टन पर जारी रहेगी।

अब 1350 रुपए में डीएपी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीएपी-आधारित उर्वरक के बैग अब 1350 रुपए में उपलब्ध होंगे, जबकि म्यूरेट ऑफ फॉस्फेट (एमओपी) उर्वरक की कीमत 1670 रुपए प्रति बैग होगी। इसी तरह एनपीके (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) का रेट 1,470 प्रति बैग में उपलब्ध होगा। 2023-24 खरीफ सीजन के लिए 38,000 करोड़ की सब्सिडी की घोषणा की गई थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में उर्वरक सब्सिडी के लिए 1.64 ट्रिलियन रुपए आवंटित किया गया, जो वित्त वर्ष 24 के लिए आवंटित 1.88 ट्रिलियन रुपये के संशोधित अनुमान से कम है।

यूरिया में आत्मनिर्भर बनेगा भारत

अभी भारत यूरिया में आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यह अभी भी अपनी रॉक फॉस्फेट की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। रॉक फॉस्फेट डीएपी और एनपीके उर्वरकों के लिए प्रमुख कच्चा माल है। भारत म्यूरेट ऑफ पोटाश के लिए आयात पर निर्भर है और सालाना लगभग 5 मिलियन टन फॉस्फेट रॉक, 2.5 मिलियन टन फॉस्फोरिक एसिड और 3 मिलियन टन डीएपी का आयात करता है। डायमोनियम फॉस्फेट के मामले में, लगभग 60 प्रतिशत आपूर्ति आयात की जाती है। 25 प्रतिशत यूरिया और 15 प्रतिशत एनपीके उर्वरक आवश्यकताओं को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है।

नई ड्रोन नीति के नियम कायदों में उलझा ड्रोन मैन अभिनव, जबलपुर छोड़कर चला गया ऑस्ट्रेलिया

नई ड्रोन नीति के कड़े नियमों से परेशान ड्रोन मैन अभिनव, जबलपुर छोड़कर चला गया ऑस्ट्रेलिया

प्रतीन नामदेव, जागत गांव हमार, जबलपुर।

नई ड्रोन नीति में इतने कड़े प्रावधान बनाए गए हैं कि केवल बड़े उद्योगपति ही भारत में ड्रोन बना सकेंगे। भारत में कोई भी आयातित ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जबलपुर के अभिनव सिंह ठाकुर ने मप्र में पहली बार 50 लीटर वजन उठाने वाले ड्रोन का इस्तेमाल करके खेती में नया प्रयोग किया था, लेकिन नई ड्रोन नीति के बाद अब अभिनव अपने काम को आगे जारी नहीं रख पाए और अंतत उन्हें भारत को छोड़कर अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला लिया।

आधुनिक खेती की समस्याएं: जो लोग खेती किसानी करते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि आजकल की खेती में कीटों का प्रकोप ज्यादा होने लगा है और कई किट ऐसे हैं जिनका तुरंत नियंत्रण न किया जाए तो वह पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। इनके कई रासायनिक और प्राकृतिक निदान भी हैं, लेकिन कृषि मजदूरों की लगातार घटती तादाद की वजह से किसान जानते हुए भी खेती में दबा का छिड़काव नहीं करवा पाता।

मध्य प्रदेश में पहला ड्रोन इस्तेमाल: जबलपुर के पाटन इलाके में एक किसान परिवार में अभिनव सिंह ठाकुर नाम के एक युवा ने इंजीनियरिंग की और जब उसने देखा कि अपने आसपास के किसान खेती में कीट पतंग के प्रकोप की वजह से अपनी आंखों के सामने फसलों को खराब होता हुआ देख रहे हैं। तो उसने काफी सोच विचार करने के बाद इस समस्या के निदान के लिए ड्रोन की तकनीक पर काम करना शुरू किया। कुछ साल पहले तक भारत में जो ड्रोन इस्तेमाल होते थे उनमें ज्यादातर छोटे ड्रोन थे, जिसमें कैमरे लगे होते थे और इन ड्रोन का इस्तेमाल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता था।

ड्रोन की क्षमता 50 लीटर तक कीटनाशक उठाने की

अभिनव ने एक बड़ा ड्रोन तैयार किया जिसके जरिए कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा सके. शुरुआत में अभिनव का ड्रोन छोटा था, लेकिन उसने लगातार कोशिश करते हुए अपने ड्रोन को 50 लीटर तक कीटनाशक उठाने की क्षमता का बना लिया। अभिनव सिंह ठाकुर ने अपने इस जुनून को ही जीवन यापन का जरिया बनाने का सोचा और उसने ऐसे और ड्रोन तैयार किया और इसके पहले कि वह इन्हें बेचने के लिए बाजार तैयार करता उससे पहले ही सरकार की ड्रोन नीति आ गई।

सरकार की ड्रोन नीति के बाद बंद हुआ उद्योग

सरकार की नई ड्रोन नीति में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसकी वजह से भारतीय ड्रोन निर्माता के सामने चुनौतियां खड़ी हो गई। सरकार किसानों को ड्रोन खरीदने की सब्सिडी दे रही है और किसानों को 5,00,000 तक की सब्सिडी मुहैया की जा रही है, इसमें एक शर्त यह है कि ड्रोन भारत में ही बना होना चाहिए। ड्रोन का आयात पूरी तरह से बंद है और कोई भी विदेश से ड्रोन आयात नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में अभिनव के सामने संकट खड़ा हो गया। क्योंकि ड्रॉन को असेंबल तो भारत में ही कर रहे थे, लेकिन इसके बहुत सारे कलपुर्जे उन्हें आयात करने पड़ते थे।

लाइसेंस की प्रक्रिया काफी महंगी

अभिनव का कहना है कि अभी जो कंपनियां प्रधानमंत्री की ड्रोन योजना के तहत किसानों को ड्रोन मुहैया करवा रही हैं वे खुद ड्रोन नहीं बना रहीं, बल्कि सामान को चोरी छुपे विदेश से आयात करती हैं और फिर उन पर अपना लेवल लगाकर उन्हें बेच देती हैं। अभिनव ने फोन पर ईटीवी भारत को बताया कि उसने भी कोशिश की थी लेकिन लाइसेंस की प्रक्रिया इतनी महंगी है कि वह इतना निवेश नहीं कर पाया।

भारत छोड़कर चला गया उत्साही इंजीनियर

इस उत्साही नौजवान ने बाकायदा एक कंपनी बना ली थी और उसे उम्मीद थी की उसकी यह कोशिश सफल होगी। लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से अभिनव अपने प्रयास को सफल नहीं कर पाया और उसने अंतत: भारत को छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया में जाकर अब वह अपने प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। अभिनव ने सोशल मीडिया के जरिए हमें बताया कि ऑस्ट्रेलिया की नीतियां ऐसी हैं कि उसका यह प्रयास वहां सफल हो जाएगा। अभिनव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए यह जानकारी उपलब्ध करवाई।

अभिनव का भारत छोड़ना नुकसानदायक

समाज में प्रयोग धर्मी कम लोग होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जोखिम उठाकर नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कई बार जोखिम उठाकर शुरुआत करने वाले असफल होते हैं, लेकिन इन्हीं उत्साही लोगों की वजह से नई तकनीक समाज तक पहुंच पाती है। लेकिन यदि ऐसे उत्साही लोगों को हतोत्साहित कर दिया जाए तो इसका नुकसान केवल उन्हें नहीं बल्कि पूरे समाज को उठाना पड़ता है। अभिनव का भारत छोड़कर जाना इस पूरे इलाके के किसानों के लिए नुकसान जनक है क्योंकि अब बहुत दिनों तक कोई ड्रोन के इस्तेमाल का जोखिम नहीं उठायेगा।

एक करोड़ परिवारों को हर महीने प्रति परिवार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की इस योजना को मंजूरी

सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार देगी 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी

जागत गांव हमार,नई दिल्ली।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। इस पर 75 हजार 21 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। योजना के तहत एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि छतों पर सोलर पैनल लगाने और एक करोड़ परिवारों को हर महीने प्रति परिवार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की इस योजना को मंजूरी दी गई है। हर परिवार को एक किलोवाट क्षमता के प्लांट के लिए 30 हजार रुपये और दो किलोवाट के संयंत्र के लिए 60 हजार रुपये सब्सिडी मिलेगी।

सरकार देश में कॉर्बन उत्सर्जन कम करने और उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। इस क्रम में मोदी सरकार ने देश के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फ्री बिजली मुहैया कराने वाली पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे हरी झंडी दिखा दी गई है। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन कहाँ करें

सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जहां इच्छुक व्यक्ति आसानी से आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति को राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar@gov.in पर आवेदन करना होगा या pmsuryaghar App डाउनलोड करके भी पंजीयन किया जा सकता है।

सोलर पैनल लगाने के लिए कितनी सब्सिडी दी जाएगी

पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार अलग-अलग किलोवॉट की सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के लिए अलग-अलग सब्सिडी प्रदान करेगी। इसमें लाभार्थी व्यक्ति को 1 से 2 किलोवॉट क्षमता वाली प्रणाली के लिए लागत का 60 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। वहीं 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक 3 किलोवाट क्षमता वाली एक प्रणाली एक घर के लिए औसतन प्रति माह 300 से अधिक यूनिट उत्पन्न करने में सक्षम होगी।

सरकार के अनुसार इससे लाभार्थी को 1 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक वाली प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही योजना में शामिल होने वाले परिवार को 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस प्रणाली की स्थापना हेतु 7 प्रतिशत के गारंटी-मुक्त कम-ब्याज वाले ऋण का लाभ भी दिया जाएगा। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दी जाएगी।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से क्या लाभ होगा

सरकार के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना की जाएगी। जिससे विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, ओ एंड एम और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही योजना से बिजली बिल बचाने के साथ-साथ डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे।

आवासीय क्षेत्र में छत पर स्थापित सौर ऊर्जा के माध्यम से 30 गीगावॉट की सौर क्षमता की बढ़ोतरी होगी

इसके साथ ही प्रस्तावित योजना के परिणामस्वरूप आवासीय क्षेत्र में छत पर स्थापित सौर ऊर्जा के माध्यम से 30 गीगावॉट की सौर क्षमता की बढ़ोतरी होगी, जिससे 1000 बीयू बिजली पैदा होगी और छत पर स्थापित सौर ऊर्जा प्रणाली के 25 साल के जीवनकाल में 720 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन में कमी आएगी।

देश के 10प्रतिशत क्षेत्रफल वाले राज्य मध्यप्रदेश में देश की लगभग 7प्रतिशत आबादी निवास करती है। यहां 11 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। राज्य की कृषि उपज में विविधता मुख्यत: नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में वर्तमान सरकार सरल नीतियों के माध्यम से 'ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस' सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है, जिससे कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश नवाचार और प्रगति के नए अध्याय लिख रहा है। 'भारत की फूड बास्केट' कहलाने वाला मध्यप्रदेश पारंपरिक प्रथाओं को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से जोड़कर देश के कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रदेश में बढ़ रहा कृषि उत्पादन, समृद्ध हो रहे किसान

डिजीटल खेती क्रांति की ओर मप्र

डेयरी प्रसंस्करण में काफी संभावनाएं

डेयरी गतिविधियाँ मध्यप्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जो रोजगार और आय के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। अधिकांश डेयरी उत्पाद दूध के रूप में बेचे जाते हैं, जिसके कारण उद्योग में मूल्यवर्धन और समग्र डेयरी प्रसंस्करण की जबरदस्त संभावनाएं हैं। वर्तमान में, राज्य के कुल डेयरी उत्पादन में दूध की हिस्सेदारी 48 है। सबसे तेजी से बढ़ते कुछ सेग्मेंट में दही, पनीर, यूएचटी दूध, फ्लेवर्ड दूध और छाछ शामिल हैं।

प्रचुर निवेश के भी अवसर

सरकारी पहल के साथ डिजिटल खेती पर केंद्रित स्टार्ट-अपके आने से विकास के लिए महत्वपूर्ण ईको सिस्टम का निर्माण हो रहा है। बेहतर बीज गुणवत्ता, उर्वरक निर्माण, कृषि मशीनरी और सिंचाई परियोजनाओं पर रणनीतिक फोकस के साथ, मध्यप्रदेश खेती के क्षेत्र में प्रचुर निवेश के अवसर प्रदान करता है।

खाद्य प्रसंस्करण में है अव्वल

वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण बाजार, जिसका मूल्य 2021 में 134.21 बिलियन है, के 2030 तक 11.82 सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र, विशेष रूप से भारत, चीन, इंडोनेशिया और मलेशिया महत्वपूर्ण वैश्विक विकास को बढ़ावा देंगे। अपने समृद्ध कृषि संसाधनों और रणनीतिक स्थान के साथ, भारत ने अपने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में तेजी से वृद्धि देखी है, जिसने 2022 में 866बिलियन डॉलर के बाजार आकार में योगदान दिया है, जो देश के आर्थिक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

जीएसडीपी में 47प्रतिशत योगदान

मध्यप्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और कृषि का राज्य के जीएसडीपी में 47 प्रतिशत का योगदान है, जो सरकार द्वारा की गई पहल का प्रमाण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सहित स्मार्ट खेती तकनीकों को अपनाकर राज्य डिजिटल खेती क्रांति की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में, सरकार सक्रिय रूप से किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का डिजिटलीकरण और कृषि आपूर्ति श्रृंखला का आधुनिकीकरण कर रही है।

सात बार जीता यह पुरस्कार

मध्यप्रदेश 'कृषि कर्मण पुरस्कार' का 7 बार विजेता है - यह पुरस्कार खाद्यान्न उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय राज्य को दिया जाता है। मध्यप्रदेश भारत में संतरा, मसाले, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य में जैविक उपज और बागवानी उत्पादन के लिए खेती का उच्च क्षेत्र है। राज्य फल, लहसुन, टमाटर, हरी मटर, अमरूद, हरी मिर्च और प्याज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और नींबू, गोभी और फूल और दूध सहित खट्टे फलों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्यप्रदेश शरबतीगेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, जिसे भारत में गेहूं की उच्चतम गुणवत्ता माना जाता है। केवल6 वर्षों में राज्य की बागवानी उत्पादन रैंकछठवें स्थान से प्रथम पर पहुंच गयी है।

लगातार हो रहा है इजाफा

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में, मध्यप्रदेश अपने समृद्ध कृषि संसाधन और रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का उपयोग करके एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। राज्य का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, 8.3ब की औसत वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जो देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उद्योग-अनुकूल नीतियों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता ने मोंडेलेज, आईटीसी और यूनिलीवर जैसे दिग्गजों से बड़े निवेश को आकर्षित किया है। पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण पहल की औपचारिकता के तहत, राज्य विभिन्न उत्पादक संगठनों को क्षमता निर्माण और समर्थन देकर असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सशक्त बना रहा है। सरकार द्वारा वित्त पोषित फूड पार्क, निजी मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण समूहों की स्थापना एक मजबूत खाद्य प्रसंस्करण ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार के समर्पण को दर्शाती है। इस क्षेत्र में कौशल विकास पर मध्यप्रदेश का ध्यान फूडइनोवेशनहब विकसित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से उजागर होता है। राज्य में पाँच प्रतिष्ठित संस्थान हैं जो संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल को शिक्षित करने और बढ़ाने के लिए समर्पित हैं।

तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक

वर्तमान सरकार के नेतृत्व में राज्य देश का तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है, जो कुल दूध उत्पादन में 8.6प्रतिशत का योगदान देता है। मध्यप्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन की उत्पादकता वृद्धि जैसी पहल, डेयरीप्रसंस्करण क्षेत्र में सतत विकास के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मध्यप्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन-शीर्ष निकाय एमपीसीडीएफ ने अकेले 2022-23 में 8.35 लाख केजीपीडी की औसत दूध खरीद और 7.16 लाख एलपीडी की औसत क्षेत्रीय दूध बिक्री और 1982 करोड़ रुपये से अधिक का बिक्री राजस्व दर्ज किया। 2020-2021 में राज्य में कुल दूध उत्पादन लगभग 20.01 मिलियन टन था। डेयरी प्रसंस्करण में शामिल प्रमुख खिलाड़ियों में अमूल (जीसीएमएमएफ), एमपीसीडीएफ (सांची), अनिक इंडस्ट्रीज (सौरभ), पवन श्री फूड इंटरनेशनल, स्टर्लिंगएग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड (नोवा) शामिल हैं।

अनुकूल नीतिगत माहौल से मजबूत समर्थन

राज्य सरकार ने उद्योग समर्थक नीतियां बनाकर इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है। वित्तीय क्षेत्र में, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को दिया जाने वाला प्रोत्साहन राज्य के अन्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन से 1.5 गुना है। राज्य सरकार राज्य में और अधिक निवेश आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और आगामी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 उज्जैन में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में राज्य की प्रगति को उजागर करेगी। मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न अवसरों और भविष्य में कृषि आय में वास्तविक वृद्धि लाने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे।

एक जिला एक उत्पाद

24 कृषि और बागवानी से संबंधित प्राथमिक उत्पाद जिनकी खेती आमतौर पर राज्य भर में की जाती है, जिनमें कोदो-कुटकी, बाजरा, संतरा/नींबू, सीताफल, आम, टमाटर, अमरूद, केला, पान, आलू, प्याज, हरी मटर, मिर्च, लहसुन शामिल हैं। अदरक, धनिया, सरसों उत्पाद, गन्ना उत्पाद, आंवला और हल्दी। छिंदवाड़ा, आगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़, मंदसौर, बैतूल और सीहोर जैसे जिले संतरे के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं जो संतरे के प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए आदर्श हैं। इसी तरह, मध्यप्रदेश के बैतूल, कटनी, अनूपपुर, रीवा, सिंगरौली और रायसेन जिले जो आम की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं, वहां कई आम आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं जो स्थापित होने के विभिन्न चरणों में हैं। राज्य सरकार ने इन जिलों की क्षमता को महसूस किया है और पहले से ही ऐसे संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है जो व्यावसायिक उपयोग के लिए जूस, जैम, स्क्वाश, सिरप, सौंदर्य उत्पाद, इत्र, सुगन्धित तेल, गूदा, सूखे आम पाउडर, चटनी, आम पना और स्टार्च जैसे प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं।

मप्र में दूध का धंधा बनेगा चंगा, सरकार पशुपालकों को देगी 5 रुपये इंसेन्टिव

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव में किसानों को लुभाने के लिए अब पशुपालकों को 5 रुपये इंसेटिव देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत राज्य सरकार दुग्ध उत्पादक किसानों को हर साल करीबन 200 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देगी। प्रदेश के वित्त विभाग ने भी इस योजना का परीक्षण कर अपनी सहमति दे दी है। राज्य सरकार की कोशिश है कि दुग्ध उत्पादन के मामले में प्रदेश को देश में पहले स्थान पर लाया जाए। इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश की 23 हजार पंचायतों में डेयरी कोऑपरेटिव समितियां गठित करने के लिए किसानों को प्रात्साहित कर रही है।

सीधे किसानों से दूध खरीद रहा दुग्ध संघ- किसानों के सामने अब दूध बेचने की समस्या नहीं रही। यदि कोई पशुपालक बड़ी मात्रा में दुग्ध उत्पादन कर रहा है तो सांची और अमूल दुग्ध संघ सीधे किसानों से दूध खरीद रही हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार पंचायतों में डेयरी कोऑपरेटिव समितियां गठित करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए पंचायतों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और दूध की बिक्री की बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव पिछले दिनों गुजरात का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान अहमदाबाद में अमूल फेडरेशन और सांची दुग्ध संघ के अधिकारियों के बीच चर्चा हो चुकी है। बैठक में सहमति बन चुकी है कि प्रदेश में अमूल फेडरेशन सीधे सांची से ही दूध खरीदेगा। इससे दोनों संघों में प्रतिस्पर्धा की स्थिति पैदा नहीं होगी।

दुग्ध उत्पादन में एमपी तीसरे नंबर पर

देश में जनसंख्या के हिसाब से दुग्ध उत्पादन देखें तो प्रति व्यक्ति 459 ग्राम दूध उपलब्ध है। देश में कुल दूध का उत्पादन 1376 मिलियन टन हो रहा है। सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। बेसिक एनिमल हसबैंड्री स्टैटिक्स के मुताबिक पिछले पांच सालों में देश में दुग्ध उत्पादन में करीबन 23 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन के मामले में देश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। इस मामले में राजस्थान दूसरे और मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन में गुजरात चौथे नंबर पर है। अब सरकार की कोशिश है कि एमपी दुग्ध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर पहुंचे।

पर्यावरण संतुलन के लिए वन्य जीवों का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी

डा. आनंद प्रकाश शुक्ला
वरिष्ठ पत्रकार

वन्य जीव हमारी धरती के अभिन्न अंग हैं लेकिन अपने निहित स्वार्थों तथा विकास के नाम पर मनुष्य ने उनके प्राकृतिक आवासों को बेदर्दी से उजाड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है और वनस्पतियों का भी सफाया किया है। धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मनुष्य को प्रकृति प्रदत्त उन सभी चीजों का आपसी संतुलन बनाए रखने की जरूरत होती है, जो उसे प्राकृतिक रूप से मिलती हैं। इसी को पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम भी कहा जाता है।

धरती पर अब वन्य जीवों और दुर्लभ वनस्पतियों की कई प्रजातियों का जीवनचक्र संकट में है। वन्य जीवों की असंख्य प्रजातियां या तो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। पर्यावरणीय संकट के चलते जहां दुनियाभर में जीवों की अनेक प्रजातियों के लुप्त होने से वन्य जीवों की विविधता का बड़े स्तर पर सफाया हुआ है, वहीं हजारों प्रजातियों के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वन्य जीव-जंतु और उनकी विविधता धरती पर अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत् विकास की प्रक्रिया का आधार रहे हैं। वन्य जीवों में ऐसी वनस्पति और जीव-जंतु सम्मिलित होते हैं, जिनका पालन-पोषण मनुष्यों द्वारा नहीं किया जाता। इन्हीं वन्य जीवों, वनस्पतियों और उनके आवासों को सुरक्षा प्रदान करने को वन्य जीव संरक्षण कहा गया है तथा इनके संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यह दिवस एक खास विषय के साथ मनाया जाता है और इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस लोगों और ग्रह को जोड़ना: वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज थीम के साथ मनाया जा रहा है। जीव-जंतुओं की तमाम प्रजातियां और वनस्पतियां मिलकर अत्यावश्यक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करते हैं और सही मायनों में वन्य जीव हमारे मित्र हैं, इसीलिए उनका संरक्षण किया जाना बेहद जरूरी है।आज प्रदूषित वातावरण और प्रकृति के बदलते मिजाज के कारण भी दुनियाभर में जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों के अस्तित्व पर दुनियाभर में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वन्यजीव दिवस मनाए जाने के उद्देश्यों में विभिन्न किस्म की वनस्पतियों तथा जीव-जंतुओं पर ध्यान केन्द्रित करना, उनके संरक्षण के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना, पूरी दुनिया को वन्यजीव अपराधों के बारे में स्मरण करवाना और मनुष्यों के कारण इनकी प्रजातियों की संख्या कम होने के विरूद्ध कारवाई करना शामिल हैं। समस्त स्थलीय और जलीय जीवों के लिए वन्य जीवों का बने रहना अत्यावश्यक है। हिन्दी अकादमी दिल्ली के सौजन्य से प्रकाशित अपनी चर्चित पुस्तक प्रदूषण मुक्त सांसें में मैंने विस्तार से यह उल्लेख किया है कि विभिन्न वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की संख्या में कमी आने से समग्र पर्यावरण किस प्रकार असंतुलित होता है। पर्यावरण के इसी असंतुलन का परिणाम पूरी दुनिया पिछले कुछ दशकों

विश्व वन्यजीव दिवस पर विशेष

से गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देख और भुगत भी रही है। लगभग हर देश में कुछ ऐसे वन्य जीव पाए जाते हैं, जो उस देश की जलवायु की विशेष पहचान होते हैं लेकिन जंगलों की अंधाधुंध कटाई तथा अन्य मानवीय गतिविधियों के चलते वन्य जीवों के आशियाने भी लगातार बड़े पैमाने पर उजड़ रहे हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस के आयोजन का निर्णय लिया गया। महासभा ने यह सुनिश्चित करने में साइट्स की महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता दी ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा नहीं है। ब्रिटिश काल से ही भारत में वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने और बचाने के लिए कानूनी प्रावधान किए जाते रहे हैं लेकिन चिंता की बात यह है कि उसके बावजूद वन्यजीवों की अनेक प्रजातियां पिछली एक सदी में लुप्त हो गई हैं। विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 में कुछ ही महीने पहले चौंका देने वाला यह चिंताजनक खुलासा भी हुआ था कि पूरी दुनिया में विगत पचास वर्षों में वन्यजीवों की आबादी करीब सत्तर फीसदी कम हुई है, जिनमें स्तनधारी, पक्षी, उभयचर, सरीसृप, मछली इत्यादि जीव शामिल हैं। हर दो साल में प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वन्यजीवों की आबादी दुनियाभर में कैसे प्रभावित हो रही है। प्रदूषण मुक्त सांसें पुस्तक के अनुसार वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए देश में सबसे पहले वर्ष 1872 में ब्रिटिश शासनकाल में वाइल्ड एलीकेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। उसके बाद वर्ष 1927 में वन्य जीवों के शिकार और वनों की अवैध कटाई को अपराध मानते हुए भारतीय वन अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसके तहत सजा का प्रावधान किया गया। देश की आजादी के बाद वर्ष 1956 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया और 1972 में देश में वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने तथा अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 लागू किया गया। वर्ष 1983 में वन्य जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव योजना शुरू की गई, जिसके तहत वन्य जीवों को इंसानी अतिक्रमण से दूर रखने और उनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय पार्क और वन्य प्राणी अभयारण्य बनाए गए। जनवरी 2003 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना तथा सजा को अधिक कठोर बना दिया गया। बहरहाल, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि वन्य जीवों का संरक्षण हम सभी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि वन्य प्राणियों की विविधता से ही धरती का प्राकृतिक सौन्दर्य है, इसलिए लुप्तप्राय: पौधों और जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियों की उनके प्राकृतिक निवास स्थान के साथ रक्षा करना पर्यावरण संतुलन के लिए भी बेहद जरूरी है।

बैंगन की फसल मे समन्वित कीट प्रबंधन

» मनोज कुमार चन्द्राकर
» भगवत शरण असाटी
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, राजनांदगांव
कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, छुईखदान

बैंगन की फसल सम्पूर्ण देश में उगाई जाती है। कभी इसे गरीबों की सब्जी कहा जाता था परंतु वर्तमान में बैंगन का बाजार मूल्य अच्छा मिलने लगा है जिससे किसान भाई अन्य उत्पाद की भांति बैंगन की खेती से अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। उपज एवं शुद्ध लाभ प्रति हेक्टेयर बढ़ाने हेतु बैंगन की खेती के लिए पौध संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

बैंगन की फसल पर लगभग 16 प्रकार के कीड़ों का प्रकोप होता है, जिनकी वजह से फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कीड़ों के नुकसान के तरीके के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं:-

1. भेदक कीट- फल एवं तना भेदक,तना छेदक आदि। **2. पत्ती भक्षक कीट**- एपिलेकना भृंग, पत्ता लपेटक, काला भृंग आदि। **3. रस चूसक कीट**- सफेद मक्खी, जैसिड,,माइट आदि। कीट एवं कीड़ों द्वारा की गई क्षति को पहचान कर इनकी उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं और उसके अनुरूप हमें कीट नियंत्रण के उपाय करने चाहिए।

1. फल एवं तना भेदक कीट की इल्ली, व्यस्क
प्रभावित प्ररोह एवं फल। **2.** एपिलेकना भृंग तना छेदक पत्ता मोड़क। **3.** मीली बगमाहू माइट जैसिड

समन्वित कीट प्रबंधन की विभिन्न विधियों का विवरण इस प्रकार से है-

- ग्रीष्मकालीन में गहरी जुताई के पश्चात नीम की खली 250 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं।
- बीज शैय्या 10 से.मी. ऊंचा बनाएं तथा उसे नायलोन नेट (40 गेज) से ढंककर रखें।
- एक ही खेत में लगातार बैंगन की फसल न लगाएं।
-मुख्य फसल के चारों तरफ मक्का (गार्ड फसल) लगाएं।

खेत में मुरझाए हुए प्ररोहों एवं क्षतिग्रस्त फलों को तोड़कर इल्लियों सहित नष्ट कर देना चाहिए। क्षतिग्रस्त पौधों, फलों को इकट्ठा कर नष्ट कर देना चाहिए। फसल कटने के बाद खेत की जुताई कर देना चाहिए जिससे मिट्टी में पड़ी शंखी नष्ट हो जायें। नवम्बर में की गई रोपाई से भेदक कीट का आक्रमण कम होता है। एपिलेकना भृंग के प्रौढ़ एवं ग्रब को संग्रहित कर नष्ट कर देना चाहिए। भेदक कीट तथा तना छेदक कीट के बचाव के लिए बैंगन फसल की पेड़ी नहीं लेना चाहिए। गहरी जुताई करने तथा खेत में सफाई रखने से सफेद मक्खी एवं तना भेदक कीटों से बचा जा सकता है। प्ररोह एवं फल बेधक कीट हेतु एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में 5 नग फेरोमोन ट्रेप लगाना चाहिए। रसचूसक कीटों के लिए पीले ट्रेप का उपयोग करना चाहिए।

शाम 7 बजे से रात्रि 9.30 बजे तक प्रकाश प्रपंच चलाकर कीटों की निगरानी करें तथा सुबह इनमें इकट्ठे प्रौढ़ों को नष्ट कर दें। खेत के अन्दर 4 से 5 मीटर की दूरी पर टी आकार की बांस की खुंटियों को गड़ा दें जिसकी लगभग ऊंचाई फसल से 30 से.मी. अधिक हो। भेदक कीट का प्रकोप गोल किस्मों में लंबे फलों की अपेक्षा अधिक होता है अत: प्रकोप के नियमित होने पर लम्बे फलों वाली सहनशील जातियां जैसे - पूसा क्रांति, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल लांग, कोयम्बटूर एफ-321,एच-158, व्हाईट 128, अर्का कुसुमाकर आदि किस्मों को लगाएं। एपिलेकना भृंग प्रकोपित क्षेत्रों में अर्का शिरीश, संकर विजय, हिसार सलेक्शन 1-4 इत्यादि किस्मों को लगाना चाहिए।

प्रकोपित क्षेत्र में भूमि की तैयारी के समय कार्बोफ्यूरान 3 जी. 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिला देना चाहिए। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम आधारित कीटनाशक तथा मैलाथियान 50 ई.सी. की 2 मि.ली. दवा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। बी.टी. (बेसीलस थुरिंजिएंसिस) जैविक कीटनाशक दवा की 1.0 - 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव भेदक कीट की रोकथाम करता है।

फल एवं तना भेदक का अधिक प्रकोप होने पर थायोडिकार्ब 75 प्रतिशत डब्ल्यू. पी. दवा की 2 ग्राम मात्रा या क्लोरअंतरानिलिप्रोल 18.5 एस.सी. दवा की 0.4 मि.ली. मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए।

रसचूसक कीटों के नियंत्रण के लिए डायमिथोएट 30 ई.सी. दवा की 2 मि.ली. दवा प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस.एल दवा की 0.2 मि.ली. दवा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। माइट के नियंत्रण के लिए प्रोपेरगाइट 57 प्रतिशत ई.सी. दवा की 3.0 मि.ली. मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए।

प्राकृतिक नियंत्रण के अंतर्गत ब्रेकान ग्रीनी, ब्रेकान चायनेनसिस एवं प्रीस्टोमीयस टेस्टासीपस परजीवी कीट इल्लियों पर परजीवीकृत कर नष्ट कर देते हैं।

रासायनिक दवा का उपयोग करते समय किसान भाई निम्न बातों पर ध्यान दें:-

1. दवाओं का छिड़काव पौधों पर समान रूप से करना चाहिए। अधिक धूप अथवा बदली के मौसम में छिड़काव/भुरकाव नहीं करना चाहिए।

2. कीटनाशी के प्रयोग के पूर्व प्रभावित कलियों तथा फलों को तोड़ लेना चाहिए।

3. दवा डालने के 15 दिनों के बाद ही फलों की तुड़ाई करनी चाहिए तथा इस्तेमाल मे लाने से पूर्व फलों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए।

4. समान समूह वाले कीटनाशक का उपयोग दुबारा नहीं करना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन से 48 देशों में आहार की कमी, जल की कमी ने बढ़ाई चिंता

दुनिया के 48 देशों में 23.8 करोड़ लोग गम्भीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। इनमें से 3 करोड़ लोग खाद्य की आपातकालीन स्थिति की चुनौतियों को झेलने को विवश हैं। इसके साथ ही खाद्य संकट से उबरने में जल की कमी ने चिंता को और बढ़ा दिया है। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म मौसम और सूखे ने पानी की कमी एवं खाद्य निर्यात पर रोक ने विभिन्न देशों की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। विश्व बैंक की खाद्य सुरक्षा अपडेट रिपोर्ट ने ऐसे शीर्ष 10 देशों की सूची जारी की है, जो खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इन देशों में कांगो में 2.58 करोड़, नाइजीरिया में 2.49 करोड़, सूडान में 2.03 करोड़, इथियोपिया में 1.9-1.99 करोड़, अफगानिस्तान में 1.99 करोड़ लोग शामिल हैं। इसके अलावा यमन में 1.7-1.79 करोड़, बांग्लादेश में 1.19 करोड़, पाकिस्तान में 1.18 करोड़, दक्षिण सूडान में 78 लाख और सोमालिया में 66 लाख लोग गंभीर आहार संकट का सामना कर रहे हैं। प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं आहार से वंचित लोग खाद्य और कृषि संगठन, एफएओ की इस वर्ष की जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया भर में 78.3 करोड़ लोग भुखमरी से ग्रसित थे। खाद्य असुरक्षा में रहने वाले लोगों की संख्या 2019 में 25.3 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष 2022 में 29.6 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2019 की तुलना में देखें तो 18 करोड़ अधिक लोग जलवायु परिवर्तन एवं जल की समस्या के कारण गभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।

हिमालयी घिंघारू, बेहद गुणकारी

हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाने वाला जंगली पौधा घिंघारू दर्द निवारण में बेहद प्रभावी पाया गया है। औषधीय गुणों के अध्ययन से पता लगा है कि घिंघारू का एंजाइम प्रभाव अन्य दर्द निवारक दवाओं से कई गुना बेहतर है। भविष्य में दर्द निवारक दवाएं बनाने में इस पौधे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह शोध दिल्ली भेषज विज्ञान एवं शोध विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। इसे जर्नल ऑफप एथनोफार्माकॉलोजी ने प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों ने पिथौरागढ़ जिले में उगने वाले घिंघारू पौधे के फल और पत्तियों पर अध्ययन किया है। इससे पता चला कि इसमें मौजूद सभी तत्व अन्य दर्द निवारक दवाओं से मिलते-जुलते हैं। इसके साथ ही इसका असर अधिक समय तक रहता है, अर्थात दर्द पर नियंत्राण करने की क्षमता इसमें ज्यादा है। प्रोटीन से भरपूर यह पौधा हिमालयी क्षेत्रों में 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसे हिमालयन फायर थार्न के नाम से जाना जाता है। घिंघारू के पौधे में छोटे फल गुच्छों में उगते हैं। सितंबर में पककर इन फलों का रंग नारंगी या गहरे लाल रंग का हो जाता है। इसके फलों का स्वाद हल्का खट्टा और मीठा होता है।

» भगवत शरण असाटी
» मनोज चन्द्राकर

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, छुईखदान
कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, राजनांदगांव

जिमीकंद की खेती किसानों को कर सकती है मालामाल

सूरन की उन्नतशील किस्मे

जिमीकंद (सूरन) की पैदावार अन्य फसलों की तुलना में कई गुना अधिक है तथा प्रति इकाई भूमि से अन्य फसलों की तुलना में अधिक आमदनी प्राप्त होती हैं। जिमीकंद के धनकन्द जमीन के भीतर बैढते हैं, अतः सूरन की फसल मे पहले बरबट्टी फिर मक्का की फसल उगाकर एक ही खेत में तीन फसलें ले सकते हैं। इसकी फसल उगाना अत्यंत सरल है एवं सिंचाई की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ती है। इसकी खेती धान खेत की मेडों पर या घर के आस पास की भूमि पर की जाती है। जिमीकंद कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है एवं विटामिन-ए, विटामिन-बी तथा लवणों से भरपूर होता है। जिमीकन्द के भूमिगत धनकन्दों का उपयोग भोज्य पदार्थ बनाने तथा आयुर्वेदिक औषधीय उपचार के लिये किया जाता है। इसके कन्दों से सूखी/रस वाली मसालेदार सब्जी, भर्ता, पापड, नूडल्स, चिप्स तथा अचार आदि स्वादिष्ट व्यंजन बनाये जाते है। यह रक्त शोधक है तथा कब्ज, बवासीर, दमा, दस्त एवं पेट के विकार आदि अनेक रोगों में लाभदायक है। जिमीकन्द की जंगली जातियों के कन्दों में कैल्शियम आक्सीलेट पाया जाता है जिसके कारण ये कन्द खाते समय मुंह, जीभ तथा गले में तीक्ष्ण खुजली एवं चरपराहट पैदा करते है।

» **गजेन्द्रा:** इस प्रजाति में सिर्फ एक ही मुख्य कंद बनता है, देशी किस्मों की तरह इसमे मुख्य कंद से जुड़े छोटे-छोटे कई कंद नहीं बनते है। इसके पौधे एवं कन्द सुडौल आकार के होते हैं तथा कंदो का गूदा हल्का नारंगी रंग का होता है। इस किस्म की उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है तथा इसके कंद खाने पर गले व मुंह में तीक्ष्णता पैदा नहीं करते है। इसकी उत्पादन क्षमता 80-100 टन प्रति हेक्टेयर है।

» **श्री पद्मा:** इस किस्म में भी एक ही सुडौल कंद बनता है तथा इसमें भी खुजलाहट/तीक्ष्णता नहीं पाई जाती है। हल्के रंग के डण्ठल इस किस्म की मुख्य विशिष्टता है। यह किस्म मोसेक रोग और कोलर मलन रोग के लिए सहनशील होती है। प्रजाति का औसत उत्पादन 40-60 टन/हेक्टेयर है।

» **संतरागाछी:** इसके पौधे बड़े एवं अच्छी बाढ़ लिए होते है। इसके मातृ कंद बाहर से खुरदुरे तथा कई पुत्री धनकंद लिए हुए कंदो के गूदे का रंग हल्का पीला होता है। इसके कंद खाते समय गले में हल्की तीक्ष्णता पैदा करते हैं। इस किस्म की उपज क्षमता 50 से 70 टन प्रति हेक्टेयर हैं।

» **भूमि और जलवायु:** पानी के अच्छे निकास वाली उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी जिमीकंद की खेती के लिए उपयुक्त होती है। फसल-वृद्धि के समय खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। मिट्टी का पी. एच. 6-8 तक होना चाहिए। जिमीकंद की फसल गर्म जलवायु में 25-35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के मध्य उगायी जाती है। आर्द्र जलवायु प्रारंभ में पत्तियों की वृद्धि में सहायक होती है तथा कंद बनने की अवस्था में सूखी जलवायु उपयुक्त रहती है। जिमीकंद की वर्षा आधारित खेती ऐसे स्थानों पर की जा सकती है, जहां 1000 से 1500 मि.मि. वर्षा होती है।

» **बीज की बुवाई का समय:** जिमीकंद आमतौर पर 6-8 माह में तैयार होने वाली फसल है तथा सिंचाई की सुविधा रहने पर इसे मध्य मार्च में लगा देना चाहिए। मार्च में लगाई फसल मध्य नवंबर तक तैयार हो जाती है। बाजार की मांग को देखते हुए 5-6 माह बाद से खुदाई शुरू की जा सकती है। पानी की सुविधा न होने पर इसे जून के अंतिम सप्ताह में मानसून षुरू होने पर लगाया जाता है। मार्च में लगाई जाने वाली फसल की पैदावार स्वाभाविक रूप से जून में लगाई फसल से अधिक होता हैं।

» **बीज की मात्रा:** रोपण के लिए भूमिगत कंदों का प्रयोग किया जाता है। रोपण के लिए 250 ग्राम से 500 ग्राम के कंदों के टुकड़े का उपयोग करने से अच्छी फसल प्राप्त होती हैं। कटे हुए टुकडे की अपेक्षा समुचे कंद का रोपण करना श्रेयस्कर होता है। बीज की मात्रा लगाने के अन्तर तथा बीज के वजन पर निर्भर करती है। एक हेक्टेयर जिमीकंद की फसल लगाने हेतु कंदो का वजन 500 ग्राम तथा लगाने का अन्तर 90 ग 90 सें.मी. रखा जाए तो लगभग 62 क्विंटल कन्दों (12346 नग) की आवश्यकता पड़ती है।

» **बीज की बुवाई एवं दूरी:** जिमीकंद की खेती करने के लिए 500 ग्रा. से 1 कि.ग्रा. तक के पूर्ण या कटे हुए कंदों के टुकड़ें उपयुक्त होते हैं। जहाँ तक संभव हो, व्यावसायिक स्तर पर खेती के लिए छोटे आकार के पूर्ण कंदो को ही प्रयोग करना चाहिए। गाय के गोबर के गाढ़े घोल में मैंकोजेब (0.2 प्रतिशत) तथा रगिंर (0.02 प्रतिशत) मिलाकर कटे हुए कंदों के टुकड़ों का उसमें डुबाकर उपचारित कर लेना चाहिए। गोबर के घोल से निकालने के बाद कंदों को उलट पुलट कर 4-6 घंटे सुखाने के बाद ही रोपण क्रिया प्रारंभ करनी चाहिए।

खाद और उर्वरक

जिमीकंद अत्यधिक उर्वरकग्राही फसल है। गोबर की खूब सड़ी हुई खाद 20-25 टन/हे. की दर से अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए। यदि गड्ढों में रोपाई की जानी है, तो गोबर की खाद को मिट्टी में मिलाकर गड्ढों में भर देनी चाहिए। रासायनिक खादों में नत्रजन, फास्फोरस तथा पोटाश की मात्रा 150:100:150 कि.ग्रा./हे. की दर से देना चाहिए। रोपाई करने के समय फास्फोरस की पूरी मात्रा तथा नत्रजन और पोटाश की आधी मात्रा देनी चाहिए। नत्रजन तथा पोटाष की बची हुई मात्रा दो बार में रोपाई के 30 तथा 60 दिन बाद खरपतवार निकाल कर पौधों पर मिट्टी चढ़ाते समय दे देनी चाहिए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नत्रजन तथा पोटाष की मात्रा 3-5 बार में देना ठीक रहता है।

सिंचाई

यदि मार्च में जिमीकंद की फसल की रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए तथा उसके बाद समय-समय पर आवश्यकता-नुसार हल्की सिंचाई करते रहनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि फसल वृद्धि की किसी भी अवस्था में खेत में पानी का जमाव नहीं रहना चाहिए। कंदों की खुदाई से पूर्व भी हल्की सिंचाई कर देने से सुविधा रहती है।

अन्तः सस्य क्रियाएं

गुड़ाई पौधों की वृद्धि तथा कंदों के विकास के लिए लाभदायक होती है। गुड़ाई के द्वारा खरपतवार भी नियंत्रित होते हैं। बारहमासी फसल होने के कारण इसमें खरपतवार समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए शस्य क्रियाएं करनी चाहिए। रोपाई के 30-35 दिनों बाद पत्ता निकल आने पर खरपतवार निकालकर नत्रजन तथा पोटाष देकर पौधों पर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। रोपाई के 60-65 दिनों बाद इस क्रिया को पुनः दोहराना चाहिए।

जिमीकंद में लगने वाले कीट एवं रोग नियंत्रण

» **याम बीटल:** ग्रब्स पत्तियों के द्वारा नाजुक डंठलों को खाते हैं। इन कीड़ों के नियंत्रण के लिए फसलों पर कार्बोरिल 50 ड्ब्ल्यू.पी. दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव लाभदायक होता है।

» **पत्ती खाने वाली सुण्डी:** इसकी सुण्डी पौधों की नई पत्तियों को खाती है, जो कि मनुष्य के उपयोग के लायक नहीं रह जाते। इस सुण्डियों को हाथ में पकड़कर खत्म कर देना चाहिए। कार्बोरिल 50 ड्ब्ल्यू.पी. दवा की 2 ग्राम मात्रा या मैलाथियान 50 ई.सी. दवा की 1 मि.ली. मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से फसलों पर छिड़काव करें।

» **कालर - राट:** पौधे के भूमि के ठीक ऊपरी भाग पर रोगजनक आक्रमण करता है और तने पर जल अवशोषित घाव उत्पन्न करते हैं। जल्द ही पूरा पौधा पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है । ऊपरी भाग सड़ने के कारण तने सिकुड़ जाते हैं। संक्रमित ऊतकों पर गोल स्क्लेरोसिया के साथ माइसीलिया की मोटी सफेद फैली हुई जाल देखी जा सकती है। शस्य क्रियाएं जैसे कि फसल-चक्र, पौध-अवशेष निवारण एवं जल निस्कासन में सुधार बीमारी के प्रकोप को कम करेगा। जैसे ही बीमारी का पहला लक्षण दिखाई पड़े पौधे के चारों ओर भूमि पर कैप्टान फफूंदीनाशक दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से महीने में दो बार अंतराल पर डालना प्रभावकारी होता है।

» **मोजेक:** पत्तियों पर धब्बे बनना (वाहक-माहू) इसका मुख्य लक्षण है। बीमारी की वृद्धि सबसे ज्यादा पार्श्व कलिका पर होती है। मातृकंदों से कलिका अलग होने लगती है और जड़ों की वृद्धि भी कम हो जाती हैं। ऐसे पौधे छोटे कंदों का उत्पादन करते है। संक्रमित पौधों को उखाड़कर फेकने से आगे बीमारीयों के फैलाव को रोका जा सकता है। मोजेक (वायरस) मुक्त कंद रोपाई के लिए प्रयोग करने, रोपाई के बाद धान के पुवाल से ढकने तथा रोपाई के 60 और 90 दिनों बाद डाइमेथोएट 30 ई.सी. दवा की 2 मि.ली. मात्रा प्रति लीटर पानी की दर दो छिड़काव करने से इस रोग पर प्रभावकारी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

» **कंदों की खुदाई एवं उपज:** रोपण के 7-10 महीने के बाद फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। पत्तियों के पीले होकर झुकना फसल के परिपक्व होने का सूचक है। ज्यादा मूल्य और पहले बाजार में लाने के लिए फसल को पूरी तरह से परिपक्व होने के पहले काटा जा सकता है। खुदाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कंद कटने न पायें। खुदाई के बाद कंदों को मिट्टी हटा कर साफ कर लेना चाहिए तथा जड़ों को तोड़ देना चाहिए। अच्छे कंदों को आकार के अनुसार छांट लेना चाहिए तथा 4-5 दिन तक छायादार स्थान पर फैलाकर सुखा लेना चाहिए। कंदो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते समय हवादार पात्र व्यवहार में लाना चाहिए। ताड़ के पत्तों से बनी डालियां में कंदों को धान के पुवाल अथवा केले के सूखे पत्तों के बीच रखकर परिवहन हेतु भेजा जा सकता हैं। जिमीकंद की पैदावार रोपाई के समय प्रयुक्त कंदो की मात्रा पर निर्भर करती हैं अच्छी फसल होने पर कंदो की मात्रा तथा पैदावार का अनुपात 1:10 का होता है। यदि 90 सेमी. ग 90 सेमी. की दूरी पर लगभग 500 ग्रा. वजन के कंद रोपाई के लिए प्रयोग किया जाते हैं तो 6 टन प्रति हेक्टेयर रोपण सामग्री लगेगी तथा 40-60 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार प्राप्त की जा सकती है। बीज उत्पादन हेतु 60 सेमी. ग 60 सेमी. की दूरी पर 100 ग्राम वजन के कटे हुए कंदों के टुकड़ों को लगाने पर 2-4 टन प्रति हेक्टेयर रोपण सामग्री लगती है तथा 15-20 टन प्रति हेक्टेयर कंद पैदावर के रूप में प्राप्त किया जा सकता हैं। अच्छे धनकंदों को आकार के अनुसार छांट लेना चाहिए तथा छोटे घनकंदों को अगली बुवाई के लिए छाया में सुखाकर, हवादार कमरों में सुरक्षित रखना चाहिए। अधिक समय तक भंडारित करने के लिए ओल के घनकंदों को 10-12 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान पर ही रखना चाहिए।

बीजग्राम योजना ने बदल दी किस्मत, दोगुना हुआ कृषि उत्पादन, आय में भी इजाफा

बीजग्राम योजना ने बदल दी किस्मत, दोगुना हुआ कृषि उत्पादन, आय में भी इजाफा

जागत गांव हमार, भोपाल।

शाजापुर जिले की शुजालपुर तहसील के कड़वाला गांव के किसान हीरालाल विश्वकर्मा प्रधानमंत्री बीजग्राम योजना से अपना उत्पादन बढ़ाकर मुनाफा ही मुनाफा कमा रहे हैं। इससे पहले वे घर के ही बीज का इस्तेमाल करते थे। इससे कई बार लागत तक नहीं निकल पाती थी, पर अब ऐसा बिलकुल नहीं है।

हीरालाल के पास 3 हेक्टेयर जमीन है। जिसमें वे खरीफ में सोयाबीन तथा रबी में गेहूं और चने की फसल लेते हैं। हीरालाल ने कृषि विभाग से प्रधानमंत्री बीजग्राम योजना से 30 किलो सोयाबीन बीज (किस्म ऋङ्कस् 2001-4) खरीफ वर्ष 2023 -24 में लिया था। उन्होंने 0.418 हेक्टेयर रकबे में यह बीज बोया तथा बीजोपचार भी कराया। पानी की कमी देखकर एक बार सिंचाई भी की तथा 100 दिन बाद फसल की कटाई हाथों से कराई। तौलने पर हीरालाल को औसतन 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिली। शुजालपुर मंडी में 5200 रुपए प्रति क्विंटल उपज बेचने पर हीरालाल को एक लाख 56 हजार रुपए मिले। प्रति हेक्टेयर लागत लगभग 50 हजार रुपए आई। हीरालाल को एक हेक्टेयर से करीब एक लाख रूपये शुद्ध मुनाफा मिला।

काम आई कृषि विभाग की सलाह

हीरालाल बताते हैं कि उन्होंने अपने दूसरे खेत में घर का बीज बोया था। तुलनात्मक अध्ययन किया, तो बीजग्राम योजना से मिले बीज का घर के बीज से लगभग दुगुना उत्पादन मिला। कृषि विभाग की सलाह का उपयोग करके हीरालाल अब सालभर में अच्छा उत्पादन ले रहे हैं।

अन्य किसानों को भी कर रहे प्रेरित

हीरालाल अब अन्य किसान भाईयों को भी सलाह देकर कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री बीजग्राम योजना अपनाएं तथा उन्नत बीज पाकर अपना उत्पादन बढ़ाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। वे इस किसान हितैषी योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री का भी आभार जताते हैं।

सरसों तिलहन समूह प्रदर्शनों का वैज्ञानिकों द्वारा भ्रमण

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार के मार्गदर्शन में डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. एसके सिंह एवं डॉ. आईडी सिंह वैज्ञानिकों द्वारा विगत दिवस ग्राम माड़ूमार में किसानों के खेतों पर सरसों तिलहन समूह प्रदर्शनों का कृषक राजेन्द्र सिंह परमार एवं अन्य कृषकों के साथ भ्रमण कर उन्हें तकनीकी सलाह दी गयी। केंद्र द्वारा रबी में सरसों की फसल पर 75 प्रदर्शन विभिन्न ग्रामों में किसानों के खेतों पर डाले गये। वैज्ञानिकों द्वारा तिलहन समूह अंतर्गत नवीन किस्म आरएच 761 दिया गया एवं इसका बीजोपचार जैविक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा 10 ग्रा./बीज की दर से कराया गया, जिससे फफूंदजनित रोगों से बचाव हुआ। आर.एच. 761 किस्म समय से बोनी एवं वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। इस किस्म में 45-55 दिनों में फूल आने लगते हैं, इसकी फलियाँ लम्बी होती हैं व फलियों में दानों की संख्या 15-18 तक होती हैं, दानों का आकर मोटा होता है, इस किस्म में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है एवं यह पाले के प्रति सहनशील है। इस किस्म की पकने की अवधि 136-145 दिन है तथा उपज 25-27 कु./हे. है। वर्तमान में सरसों की फसल में माहू कीट की समस्या देखी जा रही है, यह कीट फूल, फलियों एवं पत्तियों के रस को चूसकर फसल को कमजोर कर देता है, इसके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस.एल. 80 मि.ली./एकड़ की दर से 150 ली. पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी गई।

मधुमक्खी पालन पर वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

रीवा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात एवम काव्यश्री फाउंडेशन देहरादून, उत्तराखंड के तरफ से मधुमक्खी पालन पर सात दिवसीय वैज्ञानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनांक 22 फरवरी से 28 फरवरी 2024 का आयोजन ग्राम तिलखन, सिरमौर, रीवा में आज संपन्न हो गया। कार्यक्रम उद्घाटन के मुख्य अतिथि डॉ अखिलेश कुमार, वैज्ञानिक पौध सरंक्षण कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा और अधयक्षता वीपी सिंह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सिरमौर रीवा मप्र द्वारा किया गया। इस अवसर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विजय शंकर पांडेय भी उपस्थित रहे। डॉ कुमार ने कहा कृषकों की आय दुगना करने में मधुमक्खियों पालन एक महत्वपूर्ण घटक है। वी पी सिंह ने बताया कि मधु के साथ साथ प्राप्त होने वाले उत्पाद से भी लाभ लिया जा सकता है। मधुमक्खि पालन का ट्रेनिंग ले रहे कृषकों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किया गया। काव्याश्री फाउंडेशन के सहायक प्रबंधक भरत पटेल और फील्ड ऑफिसर महेंद्र पटेल साथ साथ मधुमक्खि पालक अरूण कुमार द्विवेदी, विंध्या बी केयर, पिपरी, सिरमौर एवं प्रगतिशील कृषक लालमनी सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अरुण द्विवेदी और धन्यवाद आदर्श द्विवेदी ने दिया।

योजनाओं और लाभों की भी मिली जानकारी

किसानों को उद्यानिकी फसलों में कीट नियंत्रण और पोषण प्रबंधन का दिया गया प्रशिक्षण

बैतूल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार में राज्य पोषित योजना अंतर्गत एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 98 किसान एवं विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन से की गई। तत्पश्चात कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। उप संचालक उद्यान राजकुमार कोरी द्वारा उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में कृषकों को संक्षिप्त में जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केन्द्र बैतूल बाजार के वैज्ञानिक डॉ. बारपेटे द्वारा उद्यानिकी फसलों पर होने वाले कीट व्याधियों पर नियंत्रण एवं उपचार के बारे में बताया गया। वैज्ञानिक डॉ. मेघा दुबे ने उद्यानिकी फसलों में खरपतवार प्रबंधन एवं फसलों में पोषण प्रबंधन के बारे में व्याख्यान दिया।

सही बीजों की ऐसे करें पहचान

कार्यक्रम में वैज्ञानिक डॉ. एम.पी. इंगले द्वारा उद्यानिकी फसलों का मूल्य संवर्धन करने के तरीकों के साथ-साथ प्रसंस्करण से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई। वैज्ञानिक डॉ. संजय जैन द्वारा उद्यानिकी की फसलों की खेती में बीज प्रबंधन एवं सही बीजों की जानकारी प्रदान की गई।

मार्केटिंग संबंधी जानकारी भी मिली

इसके अलावा वैज्ञानिक डॉ. संजीव वर्मा द्वारा उद्यानिकी फसलों के विपणन के बारे में किसानों को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में वैज्ञानिक डॉ. संजय वर्मा प्रधान उप संचालक उद्यान राजकुमार कोरी एवं वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी संतोष इवने द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

सरसों में प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन

रीवा। कृषि महाविद्यालय, रीवा के अधिष्ठाता प्रो एस के त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवम कृषि विज्ञान केंद्र रीवा म प्र के प्रमुख डा ए के पांडेय के निर्देशन में केंद्र के पौध संरक्षण वैज्ञानिक डा अखिलेश कुमार ग्राम पीपरी, सिरमौर, रीवा में कृषक अरुण द्विवेदी के खेत पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया द्य जिसमे डा कुमार द्वारा कृषकों को बताया गया कि सरसों के एक एकड़ खेत में मधुमक्खी के साथ दो बॉक्स रखा जाय तो सरसों में परागण ज्यादा होता हैं जिससे लगभग 15 से 20 प्रतिशत उपज बढ़ जाती हैं द्य साथ ही साथ अतिरिक्त उत्पाद मधु, रॉयल जेली, मौम, प्रोपोलीस, विष इत्यादि प्राप्त होती है द्य इस प्रकार कृषक मधुमक्खि पालन करके अतिरिक्त आय ले सकता है द्य इस अवसर पर गांव के प्रगतशील किसान उपस्थित रहे।

वैज्ञानिकों ने बताया आम एवं लीची में क्या करें की फल कम झड़े एवं फल विकास समुचित हो

फल लगने के बाद आम एवं लीची में वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन कर लिया जा सकता है अच्छा उत्पादन

आम को फलों का राजा एवं लीची को फलों की रानी कहा जाता है। इन दोनों फलों से अधिकतम लाभ लेने के लिए आवश्यक है की फल के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन किया जाय। आम एवं लीची में फल लग जाने के बाद यदि बाग का वैज्ञानिक ढंग से यदि प्रबंधन नही किया गया तो आशातीत लाभ नहीं प्राप्त होता है। जब आम के फल मटर के बराबर एवं लीची के फल लौंग के आकार के हो जाय तबसे बाग में हल्की-हल्की सिंचाई प्रारंभ कर देना चाहिए एवम मिट्टी को हमेशा नम बनाये रखना चाहिए, इससे फल की बढ़वार अच्छी होती है। पेड़ के आस पास जलजमाव न होने दे। बाग को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके पहले सिंचाई करने से फल झड़ने की संभावना ज्यादा रहती हैं। प्लानोफिक्स 1मिली /4लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें। जब आसमान में बादल रहेंगे तब पाउड़री मिल्डेव (चूर्डिल आसिता) रोग होने की संभानाएं ज्यादा रहती है इसके बचाव के लिए आवश्यक है कि तरल सल्फर कवकनाशक दवा ञ्च 1 मिली लीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें । इमिडाक्लोरप्रीड (17.8 एस0एल0) 1मि0ली0दवा प्रति दो लीटर पानी में और हैक्साकोनाजोल 1 मीली प्रति लीटर पानी या डाइनोकैप (46 ई0सी0) 1 मिली दवा प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़कने से मधुवा , चूर्णिल आसिता एवं एंथ्रेक्नोस रोग की उग्रता में कमी आती है। यहां यह बता देना आवश्यक है की जब अधिकतम तापक्रम 35डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के बाद चूर्णिल आसिता रोग होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है।

कीट प्रबंधन, खाद एवं दवा का उपयोग

यदि आप का आम का 10 वर्ष या लीची का पेड़ 15 वर्ष से ज्यादा का है तो उसमे 500-550 ग्राम डाइअमोनियम फॉस्फेट , 850 ग्राम यूरिया एवं 750 ग्राम म्यूरेट ऑफ़ पोटाश एवं 25 किग्रा खूब अच्छी तरह से सडी गोबर की खाद पौधे के चारों तरफ मुख्य तने से 2 मीटर दूर 9 इंच चौड़ा एवं 9 इंच गहरा रिंग बना ले ।इससे निकली हुई मिट्टी को दो भाग में बाट ले ।आधी मिट्टी में उपरोक्त खाद एवं उर्वरकों को मिला कर रिंग में डाल दे ऊपर से बची मिट्टी डाल दे,इसके बाद सिंचाई कर दे। यदि आम का पेड़ 10 वर्ष एवं लीची का पेड़ 15 वर्ष से छोटा है तो उपरोक्त मात्रा को आम के संदर्भ में 10 से एवं लीची के संदर्भ से 15से भाग दे तत्पश्चात पेड़ की उम्र से गुणा कर खाद एवं उर्वरकों की मात्रा का निर्धारण करें। जहाँ पर आम एवं लीची के फटने की समस्या ज्यादा हो वहाँ के किसान 4ग्राम घुलनशील बोरेक्स प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें या सूक्ष्मपोषक तत्व जिसमें घुलनशील बोरान की मात्रा ज्यादा हो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से फल के झड़ने में कमी आती है एवं फल गुणवत्ता युक्त होते है। यह कार्य 15 अप्रैल के आज पास अवश्य कर लें। आम एवं लीची दोनों में जिन मंजरो में फल नही लगे है, उनको काट कर बाग से बाहर ले जाकर जला दें , क्योकि अब उसमे फल नही लगेंगे एवं लगे रहने की अवस्था में ये रोग एवं कीड़ों को आकर्षित करेंगे। आम के बाग में इस समय मिली बग (दहिया कीट)कीट की समस्या ज्यादा विकट रूप से दिखाई दे रही है यदि आप ने पूर्व में इस कीट के प्रबंधन का उपाय नही किया है तो एवं दहिया कीट पेड पर चढ गया हो, तो ऐसी अवस्था में डाएमेथोएट 30 ई.सी. या नाल्फोस 25 ई.सी. 2.0 मीली दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। आम में फल मक्खी से बचाव के लिए ज्यादा बेहतर होगा की फेरोमन ट्रैप 15 से 20 ट्रैप प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें।

अनावश्यक रसायनों का छिड़काव से नुकसान

लीची में फल बेधक कीट से बचने के लिए थायोक्लोप्रीड एवं लमडा सिहलोथ्रिन की आधा आधा मिलीलीटर दवा को प्रति लीटर पानी या नोवल्युरान 1.5 मीली दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। फल का झडना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। प्रारंभिक अवस्था में जितना फल पेड़ पर लगता है उसका मात्र 4-7 प्रतिशत फल ही पेड़ पर टिकता है, बाकी फल झड़ जाता है। अनावश्यक कृषि रसायनों का छिड़काव नहीं करना चाहिए अन्यथा फायदा होने की जगह नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। आम एवम लीची का समय चल रहा है, अधिकांश किसान नही जानते है की क्या करें क्या नही करें।

यहां चलता है अनूठा बकरी बैंक, बगैर पैसे लगाए ही मालामाल हो जाते हैं किसान

कालाहांडी, एजेंसी।

कभी-कभी एक छोटी सी पहल भी बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित कर उनकी आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव ले आती है। एक ऐसी ही पहल ओडिशा के कालाहांडी में हुई है। यहां एक दंपती द्वारा शुरू किए गए बकरी बैंक ने कई गांवों के किसानों की किस्मत ही बदल कर रख दी। खास बात यह है कि इस बैंक के जरिए किसान बिना किसी निवेश के ही मालामाल हो जाते हैं। गौरतलब है कि जब पशु-पालन की बात करते हैं, तो अक्सर गाय-भैंस तक ही रुक जाते हैं। लेकिन, बकरी भी तो एक अहम पशु-धन है, जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है। देश के अलग-अलग क्षेत्रों में अनेकों लोग बकरी पालन से भी जुड़े हुए हैं। ओडिशा के कालाहांडी में बकरी पालन, गाँव के लोगों की आजीविका के साथ-साथ उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रहा है। इस प्रयास के पीछे जयंती महापात्रा और उनके पति बीरेन साहू का एक बड़ा फैसला है। ये दोनों बेंगलुरु में मैनेजमेंट प्रोफेशनल थे, लेकिन इन्होंने ब्रेक लेकर कालाहांडी के सालेभाटा गाँव आने का फैसला लिया। ये लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे, जिससे यहाँ के ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान भी हो, साथ ही वो सशक्त भी बनें। सेवा और समर्पण से भरी अपनी इसी सोच के साथ इन्होंने माणिकास्तु एग्रो की स्थापना की और किसानों के साथ काम शुरू किया। इसके साथ ही जयंती महापात्रा और बीरेन साहू ने यहाँ एक दिलचस्प माणिकास्तु त्तश्ड्डह्ल ड्ढड्डठ्ठद्म भी खोला है। वे सामुदायिक स्तर पर बकरी पालन को बढ़ावा दे रहे हैं।

इस तरह काम करता है बैंक

उनके बकरी फार्म में दर्जनों बकरियां हैं। माणिकास्तु बकरी बैंक ने किसानों के लिए एक पूरी व्यवस्था तैयार की है। इसके जरिए किसानों को 24 महीने के लिए 2 बकरियां दी जाती हैं। 2 वर्षों में बकरियां 9 से 10 बच्चों को जन्म देती हैं। इनमें से 6 बच्चों को बैंक रखता है, बाकी उसी परिवार को दे दी जाती है जो बकरी पालन करता है।

देखभाल के लिए जरूरी सेवाएं भी

इतना ही नहीं, बकरियों की देख-भाल के लिए जरूरी सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं। आज 50 गाँव के 1000 से अधिक किसान इस दंपत्ति के साथ जुड़े हैं। उनकी मदद से गाँव के लोग पशु-पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं।

पीएम मोदी ने मन की बात में किया जिक्र

इस अनूठे बैंक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने आज प्रसारित मन की बात में भी इसका विस्तार से उल्लेख करते हुए जानकारी दी। साथ ही यह कहा कि मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि विभिन्न क्षेत्रों में सफल व्यवसायी छोटे किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए-नए तरीक़े अपना रहे हैं। उनका यह प्रयास हर किसी को प्रेरित करने वाला है।

यहां जानवरों को मिलती है फाइव स्टार सुविधाएं

जानवरों के पुनर्वास को समर्पित अनंत अंबानी का प्रोजेक्ट 'वनतारा'

नई दिल्ली, एजेंसी।

देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग समारोह का जश्न 01 मार्च से जामनगर में शुरू होगा। इसी जश्न के बीच अनंत अंबानी ने जानवरों के पुनर्वास को समर्पित प्रोजेक्ट 'वनतारा' को लॉन्च किया है। रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की ग्रीन बेल्ट में वनतारा के लिए 3,000 एकड़ की जगह दी गई है। वहीं इस इलाके को हरे-भरे जंगल की तरह विकसित किया गया है। वनतारा, जानवरों को समर्पित अपनी तरह का देश का पहला कार्यक्रम है।

इस प्रोजेक्ट में अब तक 200 हाथियों सहित हज़ारों जानवरों को बचाया गया है। इनमें हर तरह का पशु, पक्षी और सरीसृप शामिल हैं। इसमें गेंडे, चीते और मगरमच्छ सहित कई प्रजातियों का पुनर्वास भी किया गया है। भारत से ही नहीं यहां विदेशों से भी उपेक्षित जानवरों को लाया गया है और उनका पूरी तरह ख्याल रखा जा रहा है।

छोटी उम्र से था मेरा सपना

वनतारा के बारे में अनंत अंबानी ने बताया कि बहुत छोटी उम्र से ये मेरा सपना था लेकिन अब वनतारा मेरे जीवन का एक मिशन बन गया है। हमारा सबसे ज्यादा ध्यान देश की सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने में लगा है। हमारे मिशन में देश-विदेश के जानवरों और चिकित्सा मामलों के कई विशेषज्ञ शामिल हैं। वनतारा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और अन्य सरकारी संगठनों के साथ पार्टनरशिप में काम करता है।

जीव सेवा, भगवान की सेवा

वनतारा के पीछे अपनी सोच के बारे में अनंत अंबानी ने कहा कि सदियों से 'करुणा' की भावना हमारी संस्कृति का अंग रही है, इस भावना के साथ हम आधुनिक विज्ञान, तकनीक और प्रोफेशनल नज़रिए को जोड़ रहे हैं। जीव सेवा, भगवान की सेवा है और इंसानियत का तकाज़ा भी।

वनतारा में फाइव स्टार सुविधा

वनतारा में हाथियों के लिए विशेष शेल्टर बनाए गए हैं। हाथियों के नहाने के लिए जगह-जगह जलाशय हैं, हाथियों के लिए जैकूज़ी और मसाज जैसी सुविधाएं भी हैं। 200 हाथियों का खयाल रखने के लिए 500 से ज्यादा प्रशिक्षित कर्मचारी और महावत हैं। वहीं एक्स-रे मशीन, लेज़र मशीन, हाइड्रोलिक पुली और क्रेन, हाइड्रोलिक सर्जिकल टेबल और हाइपरबेरिक ऑक्सीजन चेंबर और हाथियों के उपचार का तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस, एक अस्पताल भी सेंटर में खोला गया है, जो 25 हजार वर्ग फीट में फैला है। अन्य जानवरों के लिए 650 एकड़ में एक पुनर्वास सेंटर और 1 लाख वर्ग फीट का अस्पताल भी यहां बनाया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र के भवन की शुरुआत

अब फसलों में नहीं होगी बीमारियों की गुंजाइश कम होगी पेस्टिसाइड की जरूरत

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (आईपीएम) के जरिए आने वाले दिनों में ऐसी फसलें होंगी जिसमें रोग की गुंजाइश न रहे। केमिकल और पेस्टिसाइड की आवश्यकता भी कम से कम पड़े, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना बहुत जरूरी है। यही हमारे जीवन का आधार है। वो गत दिवस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र के भवन की शुरुआत कर रहे थे। यह केंद्र फसलों में लगने वाले कीटों एवं रोगों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुंडा ने कहा कि आज जरूरत अन्नदाताओं के साथ मिलकर नए भारत को गढ़ने का संकल्प लेने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण करते हुए वर्ष 2047 तक हम गर्व से कह सकें कि हम खाद्यान्न उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और हमारे यहां विदेश से दलहन-तिलहन नहीं आता। हमने प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाया है और आर्गेनिक खेती में भी सफलता अर्जित की है।

अच्छी हो खाद्यान्नों की गुणवत्ता

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस बात पर विशेष जोर है कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनें। साथ ही हमारे खाद्यान्नों की गुणवत्ता अच्छी हो। पौष्टिकता से भरपूर हो और मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहे। हमें अपनी धरती माता की सेवा करनी है। प्राचीन काल से ही हमने जमीन को भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि इसे मां का आंचल माना है। इसकी रखवाली की जिम्मेदारी भी हमारी है।

जहरीली हो रही जमीन

केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कहा कि आज हमारे यहां खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन एक समय था, जब देश में जरूरत के हिसाब से खाद्यान्न नहीं हो पाता था। तब देश में हरित क्रांति नाम से अभियान चलाया गया। इसके माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा और आज हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने समय के साथ कुछ जरूरी चीजों का मूल्यांकन नहीं किया। जिस वजह से आज महसूस हो रहा है कि जिस जमीन से हम अन्न उपजाते हैं, वह जहरीली होती जा रही है। यह मानव जीवन के लिए भी नुकसानदायक है।

कई राज्यों में बढ़ा जल संकट

आज बहुत से राज्यों में जल स्तर नीचे चला गया है, जिसके कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में हमारे सामने विकल्प क्या हैं, इसका समाधान क्या हो सकता है, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। किसान खुशहाल रहें, माताएं-बहनें आगे बढ़ें, युवाओं को अवसर मिले और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को सुरक्षा मिल सके। इस बात का सामूहिक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

एफपीओ को बढ़ावा

मुंडा ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके मातृशक्ति को समान अधिकार देने का काम किया गया है। खेती- किसानी में स्वयं सहायता समूह, एफपीओ, सहकार से समद्धि अभियान के माध्यम से समान अवसर दिया है। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन से लडने, मिट्टी की रक्षा करने, किसानों का मान बढ़ाने, छोटे किसानों तक पहुंचकर सहकार से समद्धि का आंदोलन खड़ा करते हुए खुशहाल परिवार के संकल्प को साकार किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई है।

मेले में शामिल हुए केन्द्रीय मंत्री फग्गन कुलस्ते

सिवनी के कृषि सह श्रीअन्न मेले में हुआ प्राकृतिक उत्पादों का प्रदर्शन

जागत गांव हमार, सिवनी।

सिवनी के पॉलिटेक्निक मैदान में आयोजित हुए कृषि सह श्री अन्न मेले में केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कृषि लागत में कमी तथा आमजनों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से देश में प्राकृतिक खेती के माध्यम से मोटे अनाज के उत्पादन को बढावा देने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

श्री कुलस्ते ने कहा कि हमारे पूर्वजों द्वारा आदिकाल से की जा रही प्राकृतिक खेती की पद्धति एवं मोटे अनाज स्वास्थ्य दृष्टि से लाभदायक है। उन्होंने कहा कृषक की आय में वृद्धि के लिए सरकार मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, चीना सहित अन्न मोटे अनाज को प्रोत्साहित किया जा रहा है। श्री कुलस्ते ने कहा कि सारस पोर्टल के द्वारा श्री अन्न के उत्पादन में लगे किसानों को पैकेजिंग, ब्रांडिंग की ट्रेनिंग भी सरकार द्वारा दी जा रही है।केन्द्रीय राज्य मंत्री ने श्री अन्न मेले में उपस्थित किसानों से मेले में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन कर कृषि वैज्ञानिकों से उन्नत कृषि तकनीकी एवं बीजों की जानकारी अनिवार्य रूप से प्राप्त करने की अपील की।

विदेशी बीजों को अपनाकर अनेक बीमारियों को जन्म दिया: बिसेन

सांसद डॉ. ढालसिंह बिसेन ने कहा कि अधिक उत्पादन के लालच में हमने विदेशी बीजों को अपनाकर अनेक बीमारियों को जन्म दिया है तथा अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से हमारी जमीन बंजर हो गई है तथा उत्पादित फसलों में भी पोषक तत्वों की कमी आई है। आज हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जिससे कम लागत में पोषक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। विधायक श्री दिनेश राय ने किसानों से जैविक कृषि अपनाकर उन्नत कृषि उपकरणों, बीजों एवं तकनीक को अपनाने के साथ ही कृषि भूमि का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने की बात कही। कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल ने मेले में उपस्थित किसानों को श्री अन्न मेले के उद्देश्यों के बारे में बताया तथा सभी से उन्नत कृषि तकनीकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की जानकारी लेकर तकनीकों को अपनाने की अपील की।

मेले में लगाए गए प्राकृतिक खेती के उत्पाद के स्टॉल

आयोजित मेले में कृषि विभाग के साथ-साथ उद्यानिकी, कृषि विज्ञान केन्द्र, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग आदि के स्टॉल लगाए गए थे। जिसमें में विशेष रूप से श्री अन्न फसलों के उत्पादों जैसे- कोदो, कुटकी के बिस्किट, कुकीज एवं प्राकृतिक खेती के उत्पादों के साथ छिन्दवाड़ा, मंडला के कृषक उत्पादक संगठनों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। इसके साथ-साथ सिवनी के प्रगतिशील कृषकों द्वारा जीराशंकर चांवल एवं प्राकृतिक खेती के उत्पाद, नरसिंहपुर जिले के गुड एवं तुअर की दाल के साथ-साथ अन्य जिलों के विभिन्न उत्पादकों द्वारा अपने उत्पाद का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मालती डहेरिया, जनपद अध्यक्ष सिवनी किरण भलावी, जनपद अध्यक्ष लोचन सिंह मरावी, अन्य जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में किसानों की उपस्थिति रही।

एमएसपी पर तुअर दाल खरीदेगा नेफेड, जानिए कैसे

जागत गांव हमार, नई दिल्ली।

केंद्र सरकार तुअर और मसूर के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात निर्भरता को शून्य स्तर तक कम करना चाहती है। सरकार 2027 तक दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भारत चने और कई अन्य दलहन फसलों में आत्मनिर्भर हो गया है। केवल अरहर और उड़द में थोड़ी कमी रह गई है। सरकारी संस्था नेफेड ने किसानों से तुअर दाल की खरीद की घोषणा की है। दाल की खरीद एमएसपी पर की जाएगी।

रजिस्ट्रेशन: जो किसान अपनी तुअर दाल की नेफेड को बेचना चाहते हैं, वो नेफेड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किसान मोबाइल से भी तुअर दाल और मक्का की बिक्री के लिए नेफेड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेश कराने का प्रोसेस बहुत ही आसान है।

सबसे पहले https://esamridhi#in/#/ वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन और एजेंसी रजिस्ट्रेशन दिखेगा। फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें। नेफेड पर तुअर बिक्री का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।

कैसे करता है काम: एक बार जब कोई किसान नए ई-समृद्धि प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर करता है तो वह सभी खरीदे गए और रिजेक्टेड लॉट को रिकॉर्ड करता है। प्रत्येक लॉट के लिए एक यूनिक नंबर जारी करता है और इन्वेंट्री को अपडेट करता है। उपयोगकर्ता खरीदी गई वस्तुओं की सूची देख सकते हैं। सिस्टम प्रत्येक बैग को एक क्यूआर कोड के साथ टैग करता है जिसे ई-समृद्धि खरीद पोर्टल के साथ मैप किया जाता है और इस प्रकार खरीद प्रक्रिया को आसान और सुव्यवस्थित किया जाता है।

संशोधित ई-समृद्धि प्लेटफॉर्म खरीद और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एकीकृत करता है, जिससे पीएफएमएस प्रोसेस के जरिए किसानों को सीधे भुगतान किया जाता है। किसान को डीबीटी के माध्यम से खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाता है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)